विचार बिन्दु

धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। - अरविन्द कटोच

प्राकृतिक जलवायु समाधानों के क्रियान्वयन बिना पृथ्वी पर जैव-विविधता और मानव का संकट टलना असंभव

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने हेतु पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमि का बेहतर प्रबंधन अनिवार्य है। लेकिन अभी तक की मानवीय गतिविधियों ने वैश्विक तापमान में 1.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है, और उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति से पता चलता है कि हम 10 वर्षों के पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बढ़ा देंगे। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वैश्विक वृद्धि दर धीमी हुई है और कई देशों ने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को मजबूत किया है, लेकिन वर्तमान शताब्दी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अपर्याप्त है। असल में 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये मुख्य बाधाओं की प्रकृति भू-भौतिकीय नहीं है बल्कि हमारी राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रणालियों की जड़ता है। इस जड़ता को दूर करने के लिए ऐसे राजनीतिक और कॉर्पोरेट नेतृत्व दोनों की आवश्यकता है, जो सिस्टम-स्तर और व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता की बढ़ती सामाजिक मान्यता द्वारा समर्थित हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव तो है किन्तु उपलब्ध साक्ष्य अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं देते कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। भूमि प्रबंधन हेतु उपलब्ध विकल्पों और उनकी शमन क्षमता के बारे में वैज्ञानिक स्थिति स्पष्ट करने और क्रियान्वयन योग्य बनाने के लिए "प्राकृतिक जलवायु समाधान" (एनसीएस) पर वर्ष 2017 में एक लैंडमार्क पेपर प्रकाशित हुआ था। इस शोधपत्र में संरक्षण, पुनर्स्थापन, और बेहतर भूमि प्रबंधन हेतु 20 प्रकार के विकल्प चिन्हित किये गए हैं जो कार्बन भंडारण को बढ़ाते हैं और वनों, आर्द्रभूमियों, घास के मैदानों और कृषि भूमि में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकते हैं। एनसीएस की अधिकतम क्षमता 23.8 पेटाग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष के तुल्य है। यह पिछले अनुमानों से 30 प्रतिशत अधिक है। इस अधिकतम का लगभग आधा (11.3 पेटाग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष के तुल्य) लागत प्रभावी जलवायु शमन है, यह मानते हुए कि वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण की सामाजिक लागत 100 डॉलर प्रति मेगाग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तुल्य है। प्राकृतिक जलवायु समाधान आवश्यक लागत प्रभावी कार्बन डाइऑक्साइड शमन का 37 प्रतिशत प्रदान कर सकते हैं और वर्ष 2030 तक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की 66 प्रतिशत संभावना है। इस लागत प्रभावी एनसीएस शमन का एक तिहाई 10 डॉलर प्रति मेगाग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तुल्य पर या उससे कम पर किया जा सकता है। इन शमन अनुमानों की अनिश्चितता को नियंत्रित करने के लिए शोध जारी है। फिर भी, वर्तमान में उपलब्ध प्रमाण जलवायु परिवर्तन के प्रमुख समाधान के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन में सुधार हेतु तत्काल वैश्विक कार्रवाई के लिए ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। प्राकृतिक जलवायु समाधान उन रणनीतियों और कार्यों के एक समूह को संदर्भित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रकृति और उसके पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करते हैं। ये समाधान जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में कार्य करने की प्रकृति की शक्ति को पहचानते हैं और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, बहाली और टिकाऊ प्रबंधन पर जोर देते हैं। पुनर्वनीकरण, वन संरक्षण, आर्द्रभूमि बहाली और टिकाऊ भूमि प्रबंधन जैसे प्राकृतिक जलवायु समाधानों को लागू करके, हम कार्बन पृथक्करण को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। ये क्रियाएं न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और संग्रहीत करने में मदद करती हैं बल्कि जैव-विविधता को संरक्षित करती हैं, पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं और स्थानीय समुदायों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि नेचुरल क्लाइमेट सल्यूशन ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन का विकल्प नहीं है; बल्कि, उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने और उससे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के साथ अनिवार्य रणनीति का हिस्सा हैं। इस संबंध में क्रियान्वयन को अब और पीछे नहीं टाला जा सकता। कारण यह है कि एनसीएस के सफल होने की संभावना वर्ष 2030 तक अच्छी है किन्तु बाद में, विशेषकर वर्ष 2050 के बाद, काफी हद तक घटने की आशंका है। इसके तीन मुख्य कारण हैं: जैसी कि आशंका है, जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रियाएं धीरे-धीरे पारिस्थितिक तंत्र की जैव-विविधता, मूल संरचना, इकोसिस्टम फंक्शन्स और लचीलेपन को ही कम कर देंगी, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति द्वारा कार्बन प्रथक्करण और संग्रहीत करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आ सकती है। इस बीच, यदि जीवाश्म-ईंधनों से उत्सर्जन में यथावत (बिज़नेस ऐज यूजुअल) वृद्धि जारी रही तो एनसीएस की तुलनात्मक प्रभाविता बहुत कम हो जाएगी। वैश्विक समुदाय लंबे समय से जलवायु परिवर्तन शमन के लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु ठोस क्रियान्वयन का समय आ गया है। हम यहाँ पर इस क्रियान्वयन हेतु एक श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रमाण-आधारित मार्गदर्शन उन लोगों के लिए प्रदान करेंगे जो अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की गति कम करने के लिए प्रकृति की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए क्रियान्वयन करना चाहते हैं। यहाँ यह आज स्पष्ट करना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता हानि जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में प्रमुख बाधाएँ राजनीतिक हैं। राजनेताओं और निर्णय-कर्ताओं की प्रबल और अटूट प्रतिबद्धता के बिना राजनीतिक परिदृश्य में निहित इन बाधाओं से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता है। कार्बन चक्र में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार लगभग भूमि के ऊपर 308 गीगाटन वैश्विक स्थलीय कार्बन संचित है और इन तंत्रों द्वारा लगभग 8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना संचित की जा रही है। सतह के ऊपर संचित कार्बन की हानि के मुख्य कारण वनों की कटाई, वन क्षरण, और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की बर्बादी हैं। इसके उलट वनस्पति में कार्बन सिंक का बढ़ना वन पुनर्स्थापन, वनीकरण और बेहतर वन प्रबंधन और संरक्षण आदि पर निर्भर करता है। कई नीतिगत निर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि आवास संरक्षण और पुनर्स्थापन को जैवविविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में एक साथ योगदान देते हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और जैवविविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और संयुक्त राष्ट्रसंघ का पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन दशक आदि के तहत विविध निर्णय शामिल हैं। लक्ष्य निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अच्छी तरह से संरक्षित क्षेत्र जैवविविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन जैसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बीच बढ़िया तालमेल बैठाने में कैसे योगदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में वन प्रबंधन और जैव-विविधता हानि को रोकने के लिए वन संरक्षण एक महत्वपूर्ण तंत्र है। संरक्षित क्षेत्र वैश्विक वन संरक्षण प्रयासों की नींव हैं और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी को प्राप्त करने में प्रगति निर्धारित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता की निगरानी महत्वपूर्ण है। हालांकि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव-विविधता संरक्षण पर केंद्रित है, तथापि, जैवविविधता संरक्षण से कार्बन संरक्षण का स्पष्ट सह-लाभ भी है। विशेषकर पुराने, जैवविविध वन भी प्रायः अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं। संरक्षित क्षेत्र कई क्षेत्रों में वन आवरण के नुकसान को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ तापमान और स्थानीय जलवायु को विनियमित करने और संभावित रूप से कार्बन पृथक्करण क्षमता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार जलवायु परिवर्तन शमन को बढ़ावा देने का एक उत्तम रास्ता है। अक्षुण्ण वन, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वन, वस्तुतः अधिक मानव-प्रभावित वनों और रोपित मोनोकल्चर की तुलना में दोगुना अधिक कार्बन सोख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि संरक्षित वन क्षेत्र शुद्ध वैश्विक जीएचजी सिंक का एक बड़ा अंश (लगभग 27 प्रतिशत) योगदान करते हैं, लेकिन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक और प्रवाह के परिमाण में बड़ी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर संरक्षित क्षेत्र किस हद तक कार्बन उत्सर्जन से बचने या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में योगदान करते हैं, यह अभी तक साफ़ नहीं था। अब हाल में हुई शोध इस बात को स्पष्ट करती है। नासा के जीईडीआई मिशन से सटीक लिडार डेटा का उपयोग करते हुए एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों में 61.43 गीगाटन का भारी अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक है, जो सभी स्थलीय काष्ठीय कार्बन का लगभग 26 प्रतिशत है। उल्लेखनीय यह भी है कि असुरक्षित वनों की तुलना में संरक्षित क्षेत्र अतिरिक्त 9.65 गीगाटन कार्बन का योगदान करते हैं, जो मुख्य रूप से वनों की कटाई और गिरावट के रुकने से हो रहा है। यह अतिरिक्त कार्बन भंडार लगभग एक वर्ष के वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के बराबर है। शोध के ये निष्कर्ष भविष्य में कार्बन उत्सर्जन से बचने और कार्बन पृथक्करण को संरक्षित करने के लिए उच्च बायोमास वाले वनों को प्राकृतिक जलवायु समाधान की रणनीति के अनुरूप संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की त्वरित आवश्यकता को दर्शित करते हैं (देखें, एल. डनकैंसन इत्यादि, नेचर कम्युनिकेशन्स, 14, आर्ट. 2908, 2023)। आने वाले समय में श्रृंखलाबद्ध रूप से हम प्रत्येक प्राकृतिक जलवायु समाधान का यहां विस्तृत वर्णन करेंगे जो भारत में क्रियान्वित करना आवश्यक है। भारत द्वारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के प्रकाश में प्रत्येक समाधान के योगदान पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य में जो महत्वपूर्ण क्रियान्वयन हो रहे हैं या हुए हैं उनको केस स्टडीज के रूप में भी यहां वर्णित किया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा सभी राज्य सरकारों के वन एवं पर्यावरण विभागों द्वारा प्राकृतिक जलवायु समाधान की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता दर्शित की गई है। सरकारों द्वारा किए जा रहे क्रियान्वयन को प्रमाण-आधारित बनाने के लिए अनेक वैश्विक संस्थान जानकारी साझा करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे संस्थानों का यह भी मानना है कि भारत में किये जा रहे क्रियान्वयन विश्व के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। विशेष रूप से द नेचर कंजर्वेन्सी और टेरी स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज के सहयोग से भारत के विभिन्न राज्यों में 16 राउंडटेबल्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के सहयोग से दो राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी प्रस्तावित हैं। आशा की जाती है कि ऐसे नवाचारों द्वारा उपलब्ध ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो इस ज्ञान का प्रयोग जमीन पर प्राकृतिक जलवायु समाधानों के क्रियान्वयन हेतु कर सकते हैं।

> **राजनेताओं और निर्णय-कर्ताओं की प्रबल और अटूट प्रतिबद्धता के बिना राजनीतिक परिदृश्य में निहित इन बाधाओं से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता है। कार्बन चक्र में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार लगभग भूमि के ऊपर 308 गीगाटन वैश्विक स्थलीय कार्बन संचित है और इन तंत्रों द्वारा लगभग 8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना संचित की जा रही है।**

डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त; वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं)

पुरानी योजनाएं बंद करना नई बात नहीं है

रामगोपाल जाट

नई सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुरानी सरकार की योजनाएं बंद हो जाएंगी?यह परम्परा बन चुकी है। दलों की विचारधारा ने विकास को कुंद करने का काम भी खूब किया है। बीते दो दशक से पिछली सरकार की योजनाओं पर ताला लगाने का रिवाज बना लिया है। अभी तक कमेटी नहीं बनी है, किंतु कांग्रेस सरकार की अंतिम वर्ष में शुरू की गई अधिकांश योजनाओं पर भाजपा सरकार ने अघोषित रूप से विराम लगा दिया गया है। सरकारी आदेश में सधे हुए कदमों से उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही थी।

वैसे तो इस परम्परा को शुरू करने का काम 1998 के दौरान किया गया था। फिर 2003 में इसको आगे बढ़ाया गया। 2008 में इस परम्परा को मजबूती मिली और 2013 में निःशुल्क दवा और जांच योजना की तस्वीर बदकर परम्परा को पुख्ता किया गया। पांच साल पहले योजनाओं को बंद करने और उनका नाम बदलने का क्रम आरम्भ हुआ।

अन्नपूर्णा रसोई, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों को मिलने वाले बिजली अनुदान जैसी योजनाओं का नाम बदला गया। यह बात भी सही है कि अधिक प्रचलित मानी जारी वाली योजनाओं को आखिरी वर्ष में शुरू कर चुनावी लाभ का कारोबार किया जाता है। अब फूड पैकेट, महिलाओं को मोबाइल, 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट के अलावा आरजीएचएस और चिरंजीवी को लेकर बंद करने की सुगबुगाहट ने वोटर्स के कान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के मन में ओपीएस को लेकर सबसे अधिक चिंता है, जिसका कानून बनाने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। हालांकि, यह योजना मधुमक्खियों के छत्ते के समान है, जिसमें हाथ डालते हुए कार्मिकों के डंक लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। बाकी योजनाओं पर जनता की कितनी प्रतिक्रया होगी, यह तो समय बताएगा। आरजीएचएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो रही है, इसलिए सरकार इसका क्या करेगी, यह भी विचारणीय विषय है।

नई सरकार ने आदेश जारी कर सभी नए टेंडर रोक दिए गए हैं। पुराने टेंडर भी अब लंबित रहेंगे। अग्रिम आदेश का मतलब यही है कि पुराने सभी टेंडर की जांच करके ही आगे बढ़ा जाएगा। वर्तमान में राज्य के खजाने से 30 हजार करोड़ के बिल लंबित पड़े हैं। सरकार पर 5.59 लाख करोड़ का कर्जा है। बीते पांच साल में कर्ज 3.36 लाख करोड़ से बढ़कर यहां तक पहुंच चुका है। सरकार के पास प्रतिवर्ष आय 1.40 लाख करोड़ है, जबकि कर्ज को चुकाने के लिए भी उधार लिया जा रहा है। सरकार चलाने और फ्री रेवड़ियां बांटने के लिए रिजर्व बैंक से प्रतिभूति जारी करवाने का काम युद्ध स्तर पर किया गया। नई सरकार को इस बात की जांच कर सार्वजनिक करना चाहिए कि सरकार की कितनी संपत्तियां गिरवी रख दी गई हैं।

सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार के बाद खजाने पर बोझ की चुनौती सबसे चुनौतीपूर्ण है। यह बात सही है कि सरकार की फ्री योजनाओं को बंद करना आसान काम नहीं है, खासकर जब चार महीने बाद आम चुनाव हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पूर्व सरकार की सभी योजनाएं कम से कम मई महीने तक यथावत चलेंगी, उसके उपरांत निर्णय लिया जाएगा। डिस्कॉम पर 2018 तक कोई कर्ज नहीं था, लेकिन आज 76 हजार करोड़ का ऋण है, जो हम महीने करीब 15 हजार करोड़ बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट का लाभ डिस्कॉम को कंगाली की तरफ ले जा रहा है। बिजली छीजत रोकने का काम बिलकुल निम्न स्तर पर चला गया है। कमर्शियल कनेक्शन के साथ सबसे अधिक बिजली छीजत चल रही है। अधिकारी और कर्मचारी कितना लाभ ले रहे हैं, इसकी भी जरूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

इंदिरा रसोई को अन्नपूर्णा किया जाएगा, चिरंजीवी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आरजीएचएस पर तलवार लटक रही है तो ओपीएस के लिए केंद्र सरकार को निर्णय करना है। फूड पैकेट और महिलाओं को मोबाइल पर अघोषित रोक लग गई है। चिरंजीवी योजना प्राइवेट अस्पतालों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। बीते 15 साल से सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को डंप करने का काम किया है। इस बात की तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि निजी अस्पतालों में किस-किस पूर्व सीएम का कितना हिस्सा है? किस नेता या अधिकारी की कितनी साझेदारी है? यदि इसकी ही ईमानदारी से जांच हो जाए तो पता चला जाएगा कि सार्वजनिक चिकित्सा की इतनी बुरी गत क्यों हुई है।

आंगनबाड़ी से लेकर दवा योजना और फूड पैकेट से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं की जांच और हर समय मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक सरकारी घाटा कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। सीएम का चेहरा तो 25 साल बाद नया मिल गया, किंतु प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण ब्यूरोक्रेसी क्या खेल करेगी, इसके ऊपर जब तक केंद्र सरकार निगरानी नहीं होगी, हर आदेश को जांचा परखा नहीं जाएगा, तब तक नयेपन की उम्मीद करना बेकार है। मंत्रियों के बनने के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी को काम करना है।

सीएम ने अधिकारियों को आश्वस्त तो कर दिया कि पूर्वाग्रह के बिना काम करेंगे, लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी ने प्रदेश का यह हाल किया है, इसलिए ईमानदार अधिकारियों की टीम बनाकर उनको निगरानी के लिए रखना होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी केवल अधिकारियों के भरोसे सरकार चलाई तो पांच साल बाद भाजपा को फिर से विपक्ष में बैठने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए।

रामगोपाल जाट
वरिष्ठ पत्रकार

'देश की तरक्की का मार्ग खेत व खलिहान से ही होकर निकलता है'

केन्द्रीय संस्थान अविकानगर में किसान दिवस पर राष्ट्रीय किसान संगोष्ठि आयोजित

> ■ **राजस्थान के किसान व पशुपालक पहुंचे, महिला पशुपालक साधना गुलेरिया को मिला किसान रत्न अवार्ड**

मालपुरा, (निसं)। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती एंव किसान दिवस के अवसर पर शनिवार को केन्द्रीय भेड एंव ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर सभागार में राष्ट्रीय किसान संगोष्ठि का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवल्लित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

राष्ट्रीय किसान संगोष्ठि में राजस्थान के कोने-कोने से 500 से अधिक किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया। जिनमें दौसा जिले के अनुसुचित जाति परियोजना के 50 लाभार्थी किसान भी शामिल रहे। विधायक ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि खेत व खलिहान से ही होकर निकलता है देश की तरक्की का मार्ग। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानो को देश का उन्नत किसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम आवास योजना, उज्जवला गैस योजना, घर-घर नल कनेक्शन सहित अनेक योजनाऐं शुरू की है। जिनका लाभ गांव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

विधायक ने अविकानगर संस्थान निदेशक डॉ. अरूण कुमार तोमर के सुपरविजन मे संस्थान के वैज्ञानिको द्वारा लम्बे सोच के बाद तैयार की गई अविशान भेड की नस्ल की देशभर मे हो रही बैहद मांग पर खुशी जाहिर कर इस उपलब्धि को अविकानगर सहित मालपुरा विधानसभा क्षैत्र के हर नागरिक का गौरव बढ़ाया है। विधायक ने संस्थान की वैज्ञानिक तकनिकीयो का लाभ लेकर भेड, बकरी व खरगोश के साथ-साथ गाय पालन को बढ़ाने की अपील की। मंच के माध्यम से विधायक ने अवगत करवाया कि राजस्थान मे ईस्टर्न कैनल नहर परियोजना ईआरसीपी को जल्द अर्थात दो महिने मे केन्द्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर कार्य शुरू करवा देगी। जिससे राजस्थान के साथ-साथ टोंक जिला व मालपुरा विधानसभा क्षैत्र के किसानों को लाभ मिलेगा व उनका सपना साकार होगा।

डॉ. तोमर ने कहा कि संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक द्रष्टि से खेती व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान से जुडे 60 गांवो के साथ-साथ डुंगरपुर, बाडमेर, उदयपुर, दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ आदि क्षैत्रों में उन्नत नस्ल के पशुओं का वितरण, गिर गाय के कृत्रिम गर्भाधान, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, आयोजित किये जा रहे है।

ईफको के प्रशासनिक अधिकारी सुधीर मान ने खेतों में वैज्ञानिक पद्धति से नैनो डीएपी व यूरिया का उपयोग कर कम समय व कम लागत मे अधिक उपज लेने की जानकारी दी। अविकानगर संस्थान से सिरोही नस्ल की दस बकरियां ले जाकर बकरियों का बडा रेवड तैयार करने के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढावा देने वाली महिला किसान को साधना गुलेरिया को डॉ. आरएस परोधा किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित कर 21 हजार की राशि का चैक व प्रशंसा पत्र दिया गया व मालपुरा क्षैत्र के अन्य क्षैत्रों का चयन दस प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित कर प्रति किसान 2100 रूपये प्रोत्साहन राशि का चैक दिया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठि के समन्वयक डॉ. लीलाराम गुर्जर ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला।

अतिथियों ने फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंगीकृत गांवो के भेड पालकों को नस्ल सुधार के लिए 5 पाटनवाडी व मालपुरा नस्ल के मेंढो का वितरण किया गया व मालपुरा तहसील के 18 किसानों को आजीविका के लिए सिरोही नस्ल की बकरियों का वितरण किया गया। इस दौरान डॉ. नन्दलाल सेपट, अध्यक्ष फार्मर फोरम, खेमाराम महरिया, बीएल मंडीवाल भी मंचाशील रहे। डॉ. अमर सिंह सहित संस्थान निदेशक व वैज्ञानिकों ने अतिथियों को ऊन से बना गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

शिल्पग्राम उत्सव: ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक नृत्य से कलाप्रेमी मंत्रमुग्ध

> ■ **कुचिपुड़ी नर्तकों-नृत्यांगनाओं ने 'जाति स्वरम' की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।**

उदयपुर, (निसं)। शिल्प और कला का महोत्सव शिल्पग्राम उत्सव धीरे-धीरे परवान पर चढ़ रहा है। यहां लोक कला व संस्कृतियों की कलाकारों द्वारा मुक्ताकाशी रंगमंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही है जो कलाप्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। शिल्प के आंगन में भीड़ बढती जा रही है। रविवार अवकाश का दिन होने के साथ ही यहां अब भीड़ ज्यादा जुटने लगेगी। शिल्पग्राम उत्सव में शनिवार को मुक्ताकाशी रंगमंच पर कुचिपुड़ी नृत्य के अंतर्गत 'शित तरंगम' की प्रस्तुति हुई। जिसमें कलाकारों ने पीतल की थाली पर नृत्य करते हुए शिवाराधना करते संतुलन दिखाया तो सभी आश्चर्यचकित और सन्न रह गए।

आंध्र प्रदेश के इस डांस में जब कुचिपुड़ी नृत्य के विश्व प्रसिद्ध गुरु वी. जयराम राव ने प्रस्तुति दी तो तालियों की गड़गड़ाहट से शिल्पग्राम गूंज उठा। राव पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके साथ ही कुचिपुड़ी नर्तकों-नृत्यांगनाओं ने 'जाति स्वरम' की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें कर्नाटक संगीत पर स्वरों का सम्मेलन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की वेशभूषा और ज्वेलरी पहने डांसर्स ने मंदिरों में स्तुति की भाव भंगिमाओं का नयनाभिराम प्रदर्शन किया। इससे पूर्व, पद्मश्री व संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजी जा चुकीं विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा फिल्म निर्मात्री रंजना गौहर के ग्रुप ने ओडिसी डांस 'रास रंग' को पेश कर सम्मोहित कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित इस नृत्य में बेहद खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ सभी डांसर्स ने श्रीराधा-कृष्ण और गोपियों के कुंज वन के रास की जीवंत प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

नामचीन कथक नृत्यांगना लखनऊ घराने की मालती श्याम एंड ग्रुप ने कथक की शानदार प्रस्तुति से सुधी दर्शकों को थिरकने पर विवश कर दिया। यह नृत्य तीन ताल ख्याल में पेश किया गया। इसमें बहुत ही नयनाभिराम भावभंगिमाओं के साथ तोड़े, टुकड़े और तिहाइयों का प्रयोग किया। अंत में इन तीनों सिद्धहस्त डांसर्स के ग्रुप्स की संयुक्त प्रस्तुति 'तराना' ने शिल्पग्राम की शाम को शास्त्रीय बना दिया। तीनों अलग-अलग विधाओं के सुपर सम्मिलन ने हर कला प्रेमी का मन मोह लिया।

मुक्ताकाशी मंच पर शनिवार शाम 'महाराष्ट्र दिवस' को साकार कर दिया। 'लोक झंकार' के अंतर्गत महाराष्ट्र के तमाम लोक नृत्यों ने गजब का समां बांधा। इस प्रस्तुति के दौरान लावणी और शिवाजी महाराज के साथ ही गान, गावलोन, वासुदेव, शेतकारी, ठाकर, जोगवा, गोंडल, सोंगी मुखौटा, कोली, डींडी और महाराष्ट्र गीत ने महाराष्ट्र की लोक संस्कृति को साकार कर दिया।

जालोर राजकीय चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था चरमराई

> ■ **चिकित्सालय में सफाई कार्मिकों को ठेकेदार ने दो माह से मानदेय नहीं दिया**

जालोर, (कासं)। जालोर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय में हनुमान सेवा समिति नाम की निजी संस्था के माध्यम से लगे ठेका सफाई कार्मिकों को दो-तीन माह से मानदेय नही मिलने पर सफाई व्यवस्था का बहिष्कार करने से अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए है। ऐसे में सफाई कार्मिकों के द्वारा सफाई नही करने से अस्पताल में गंदगी से बदबू के चलते मरीज परेशान है।

जालोर के राजकीय चिकित्सालय में लम्बे से एक ही निजी संस्था हनुमान सेवा समिति द्वारा सफाई का ठेका देने से निजी संस्था द्वारा ठेके पर रखे गये सफाई कार्मिको को दो-तीन माह से मानदेय नहीं देने से अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा सी गई है। वहीं हनुमान सेवा समिति संस्था द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने से अस्पताल में जगह जगह गंदगी पसरी होने से मरीज व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेका सफाई कार्मिकों ने जिला कलैक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि हनुमान सेवा समिति नाम की निजी संस्था के मुखिया वचनाराम गर्ग ने उप ठेका भरत कुमार गांव पाथेडी को दिया हुआ हैं। पिछले दो तीन माह से निम्न व दिहाड़ी मजदूर सफाई कार्मिकों को मानदेय नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। मानदेय नहीं मिलने पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष वचनाराम गर्ग, उप ठेकेदार भरत व जालोर अस्पताल के पीएमओ को बताने पर हमें मानदेय दिलाने की बजाय उल्टा हमे ही फटकार लगाते हुए निकाल देते है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

रविवार, 24 दिसम्बर 2023

मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, विक्रम सम्वत 2080, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 9.14 तक, साध्य योग सोमवार प्रातः 5.41 तक, कौलव करण सायं 6.01 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृष, मंगल-वृश्चिक, बुध-धनु, गुरु-मेष, शुक्र-तुला, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा।

रवियोग रात्रि 9.19 से आरम्भ होगा। आज महापात योग दिन 12.08 से सायं 6.52 तक रहेगा। आज प्रदोष व्रत है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चर 8.34 से 9.52 तक, लाभ-अमृत 9.52 से 12.26 तक

राहुकाल - 4.30 से 6.00 तक, सूर्योदय 7.17 सूर्यास्त 5.31

मेष

अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। पारिवारिक कार्यों के कारम भाग दौड़ रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क

आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।

सिंह

अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। सामुहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

धनु

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर

आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

कुंभ

अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।